उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 16 | 16-31 अगस्त 2021 | ₹ 20/-

रसूल और कुरान के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के प्रयास

- दारूल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाने की मांग
- अफगानिस्तान में सह शिक्षा पर प्रतिबंध
- यमन में हूती विद्रोहियों का हमला
- कांग्रेस का बदरूद्दीन अजमल की पार्टी से संबंध विच्छेद

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

रसूल और कुरान के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के प्रयास 04
अलीगढ़ का नाम बदलने पर विवाद 06
दारूल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाने की मांग 08
मस्जिदों में नमाज पढ़ने का विवाद 11
उत्तर प्रदेश के बारह जिलों में खुलेंगे एटीएस कमांडो सेंटर 13

विश्व

अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी सैनिक भी वापस 14
जर्मनी द्वारा अफगानिस्तान को सहायता देने से इंकार 15
अफगानिस्तान में सह शिक्षा पर प्रतिबंध 16
तालिबान का धार्मिक प्रमुख 17
अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन पर प्रतिबंध 17
चीन में तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति 17

पश्चिम एशिया

उमरा करने की अनुमति 18
यमन में हूती विद्रोहियों का हमला 19
मलेशिया के नए प्रधानमंत्री 19
माली के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार 19
सऊदी अरब और रूस के बीच सैनिक संधि 20
मिस्र में पार्ट टाइम शादी पर प्रतिबंध 20

अन्य

कांग्रेस का बदरूद्दीन अजमल की पार्टी से संबंध विच्छेद 21
22 हजार से अधिक मदरसा अध्यापक वेतनमान से वंचित 21
सिकंदर बख्त की मजार पर श्रद्धांजलि सभा 22
मुस्लिम विद्वानों से टीवी चैनलों का बहिष्कार करने की अपील 22
ब्रिटेन से ताजिया का मॉडल मंगवाने की मांग 22

सारांश

विभिन्न राज्यों में चुनाव की हलचल शुरू होते ही कुछ मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों को भाजपा सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। वे इस तथ्य को भलीभांति जानते हैं कि कुरान और पैगम्बर के मामले में मुसलमान अति भावुक होते हैं इसलिए उनकी भावनाओं को इन मुद्दों की आड़ लेकर आसानी से भड़काया जा सकता है। इससे पूर्व भी पैगम्बर की कथित तौहीन की आड़ लेकर इस देश में अनेक बार हिंसक दंगे भड़काए जा चुके हैं। हाल ही में तहरीक फरोग-ए-इस्लाम नामक एक नया संगठन मैदान में उतरा है। इसका मुख्यालय दिल्ली के जाकिर नगर (ओखला) में है। इसके अध्यक्ष मौलाना कमर गनी उस्मानी पहली बार चर्चा में आए हैं। हालांकि यह बात सच है कि पिछले एक वर्ष से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बरेलवी मुसलमानों का एक वर्ग पैगम्बर और इस्लाम के तौहीन की आड़ लेकर जनभावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है। बरेली दरगाह के आला हजरत तौकीर रजा द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किए जाने के कारण यह मामला गंभोर रूप ले सकता है।

इस हकीकत को कौन नहीं जानता कि तालिबान के तार दारूल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हैं। देवबंदी सम्प्रदाय की वहाबी विचारधारा किसी से छिपी हुई नहीं है। देश के विभाजन के बाद देवबंदियों का एक गुट पाकिस्तान चला गया था, जिसने वहां पर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम का गठन किया। इस संगठन के साथ तालिबान सहित चार अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के तार जुड़े हुए हैं। देवबंद के कर्ताधर्ता प्रायः स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम उलेमा के योगदान की जोर-शोर से चर्चा किया करते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम से इनका कभी कोई संबंध नहीं रहा है। इनका एक मात्र लक्ष्य इस देश में पुनः इस्लामिक हुकूमत की स्थापना करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बारह मुस्लिम बहुल जिलों में आतंकवाद निरोधक केन्द्र स्थापित करने का जो निर्णय किया है वह इन दिनों विपक्षी दलों के निशाने पर है। आने वाले चुनाव में विपक्षी दल उसका राजनीतिक लाभ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका यह प्रयास कितना सफल होता है अभी इस संबंध में कुछ भी कहना कठिन होगा।

अलीगढ़ जिला पंचायत ने अलीगढ़ जिला का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की राज्य सरकार से जो सिफारिश की है उसे अतिवादी मुस्लिम संगठनों ने पसंद नहीं किया। इससे पूर्व भी ये संगठन इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का मुखर विरोध करते आ रहे हैं। प्रश्न यह पैदा होता है कि जिन विधर्मी विजेताओं ने तलवार के बल पर प्राचीन नामों को बदल डाला था क्या उन्हीं नामों को जारी रखना उचित होगा?

20 वर्षों के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर लौट गया है और वहां पर तालिबान सत्ता में आ गए हैं। भारत सरकार ने तालिबान के साथ अनौपचारिक वार्ता के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अभी यह कहना कठिन है कि अफगानिस्तान की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेती है।

सऊदी अरब ने डेढ़ वर्ष पूर्व कोरोना महामारी के चलते हज और उमरा पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटाने की घोषणा कर दी है। अब विश्व भर के लोग उमरा करने के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे।

रसूल और कुरान के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के प्रयास

तहरीक फरोग-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना कमर गनी उस्मानी ने प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बात की धमकी दी है कि अब मुसलमान सिर पर कफन बांधकर मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब हम कुरान और रसूल का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंग। इस संबंध में देश भर में मुसलमानों की ओर से जबर्दस्त आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान लाइव के अनुसार उन्होंने कहा कि हाल ही में देश भर में रसूल और कुरान की तौहीन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। रसूल और कुरान हमें बेहद अजीज हैं। हम इनके लिए अपनी जान दे सकते हैं मगर इनका अपमान किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में मॉब लिंचिंग द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि सरकार इन मुस्लिम विरोधी गतिविधियों को रोकने में अभी तक विफल रही है। अब हमारे सामने इंसाफ के लिए सड़क पर उतरने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है।

इंकलाब (25 अगस्त) के अनुसार दिल्ली में तहरीक फरोग-ए-इस्लाम की एक बैठक हुई थी, जिसमें मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी और उनमें बढ़ रही असुरक्षा की भावना की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आयोजन करने की घोषणा की गई थी। मौलाना उस्मानी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोकने के लिए गैरकानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अगस्त) के अनुसार रजा एकेडमी के संस्थापक मोहम्मद सईद नूरी ने यह आरोप लगाया है कि फिल्म नवारसा में कुरान पाक की तौहीन की गई है। इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंची है। उन्होंने मांग

की कि इस साजिश के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सरकार तुरंत सख्त कार्रवाई करे।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 अगस्त) में अब्दुल बारी खान का एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मुसलमानों को इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है और उन्हें जान व माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा उनके खिलाफ झूठा प्रचार हो रहा है। मदरसों पर पाबंदी लगाई जा रही है और शरई कानूनों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कुछ शरारती तत्वों ने पैगम्बर इस्लाम और कुरान को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसको रोकने के लिए भीम राव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कानून का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि पैगम्बर इस्लाम और अन्य धार्मिक नेताओं की तौहीन करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। इसके प्रारूप को 17 जून को मुंबई पत्रकार संघ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जारी भी किया गया था। इस संबंध में महाराष्ट्र विधान सभा में 6 जुलाई को इस विधेयक को पेश भी किया गया था मगर मुस्लिम नेताओं ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि हम यह प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इस प्रारूप को पेश करें।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 अगस्त) के अनुसार बरेली दरगाह के सज्जादानशीन तौफीक रजा खान ने यह मांग की है कि रजा अकेडमी ने पैगम्बर-ए-इस्लाम के अपमान को रोकने के लिए जो विधेयक का प्रारूप तैयार किया है उसे भारत सरकार को फौरन स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरेलवी सम्प्रदाय इस कानून को पास करवाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे चुनाव में सिर्फ उसी मुस्लिम नेता को अपने वोट दें जो कि इस प्रारूप का सदन में समर्थन करने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति पैगम्बर, कुरान या किसी अन्य धर्म के संस्थापक का अपमान करता है उसके लिए फांसी या उम्रकैद का प्रावधान होना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 अगस्त) के अनुसार मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद श्रीमती सुप्रिया सुले से मुलाकात की और उनका ध्यान देश में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए वातावरण की ओर दिलाया और मांग की कि इस संबंध में वे संसद में प्रस्तावित विधेयक को प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी मांग की कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को शिक्षा संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।

इंकलाब (29 अगस्त) के अनुसार तहरीक फरोग-ए-इस्लाम के अध्यक्ष कमर गनी उस्मानी ने देश में मुस्लिम विरोधी अभियान पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से मांग की है कि दीन, इस्लाम और पैगम्बर की शान में गुस्ताखी करने वालों और देश में साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस संदर्भ में एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भी भेजा है। उस्मानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ही इस्लाम के खिलाफ विष वमन और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर चोट करने का अभियान शुरू हो गया है और दु:ख की बात यह है कि ऐसे तत्वों को भारत सरकार संरक्षण प्रदान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का नारा देते हैं। दूसरी ओर, पैगम्बर की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद को सुरक्षा प्रदान की जाती है और मुसलमानों के

खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। मुफ्ती अख्तर रजा मजादी ने कहा कि बहुसंख्यकों को यह कहकर भ्रमित किया जा रहा है कि उन्हें अल्पसंख्यकों से खतरा है। उन्होंने धमकी दी कि अगर मुस्लिम दुश्मन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमें मैदान में उतरना होगा।

अलीगढ़ का नाम बदलने पर विवाद

अवधनामा (18 अगस्त) के अनुसार योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों का नाम बदलने का जो अभियान चल रहा है अब उस सिलसिले में अलीगढ़ का भी नाम बदलने की तैयारी है। अलीगढ़ जिला पंचायत ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का फैसला किया गया है। इस प्रस्ताव को कहरी सिंह और उमेश यादव ने बैठक में पेश किया था, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। अब मैनपुरी का नाम भी बदलने की तैयारी हो रही है। उसका नाम मयन ऋषि के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिला था। मगर जब उसे बैठक में पेश किया गया तो उसका विरोध कई सदस्यों ने किया। अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया ने मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने के सुझाव को मान लिया। अब इन प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति के लिए योगी सरकार के पास भेजा जाएगा। अलीगढ़ में इस समय स्वर्गीय कल्याण सिंह की समधन जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। वहीं मैनपुरी जिला पंचायत पर भी पहली बार भाजपा ने कब्जा किया है।

इससे पूर्व भी 1992 में कल्याण सिंह के शासनकाल में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रयास किया गया था। मगर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। इससे पूर्व योगी सरकार सत्ता में आने के बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर चुकी है। इसके अतिरिक्त खलीलाबाद का नाम संत कबीर नगर रखा जा चुका है।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा फिरोजाबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद और अहमदाबाद

आदि अनेक नगरों का नाम बदलने का प्रयास कर रही है। इसका लक्ष्य भारत से इस्लाम और मुसलमानों की निशानियों को मिटाना है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि योगी सरकार क्योंकि सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है। इसलिए आने वाले विधान सभा चुनाव में वह साम्प्रदायिक मुद्दे उठाकर बहुसंख्यक मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना चाहती है।

सियासत (19 अगस्त) ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए विभिन्न नगरों का नाम बदल रही है। नवंबर 2019 में जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था तो उसकी जबर्दस्त आलोचना हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने वही किया जो हमें अच्छा लगा। जहां जरूरत होगी वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हमारा समाज (19 अगस्त) ने अलीगढ़ का नाम बदलने की तीव्र आलोचना की है। सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा है कि पूरी दुनिया में अलीगढ़ की पहचान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वजह से है। मगर अब साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए फिजूल के मामले उछाले जा रहे हैं। यूपी राबिता कमेटी के सचिव डॉ. उबैद इकबाल ने कहा है कि कुछ साम्प्रदायिक तत्व ऐसे शोशे छोड़कर चुनाव जीतने की भूमिका बना रहे हैं। मगर प्रदेश की जागरूक जनता इन ओछे हथकंडों को सफल नहीं होने देगी। अलीगढ़ के वकील नसीम अंसारी का कहना है कि योगी के शासनकाल में क्योंकि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है इसलिए अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के नए शोशे छोड़े जा रहे हैं।

इंकलाब (4 अगस्त) के अनुसार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को सूचित किया है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की मांग की गई है। इससे पूर्व फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने की मांग भी वहां की जिला पंचायत कर चुकी है।

इंकलाब (3 अगस्त) के अनुसार फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्र नगर रखने का प्रस्ताव जिला पंचायत में ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने पेश किया था जिसे मंजूर करने के बाद जिलाधिकारी को भेजा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस नगर का मूल नाम चंद्र नगर ही था जिसे 1556 मं अकबर के शासनकाल में बदलकर फिरोजाबाद कर दिया गया था। जबकि इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि फिरोजाबाद का मूल नाम चंद्र नगर कभी नहीं रहा है। इस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और उसी ने इसका नाम फिरोजाबाद रखा था। अब साम्प्रदायिक तत्व राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जानबूझकर इसका नाम चंद्र नगर रख रहे हैं।

इंकलाब (1 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का विरोध करते हुए 'द वायर' के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा है कि मथुरा में 18 प्रतिशत मुसलमान और 20 प्रतिशत दलित रहते हैं जो कि मांसाहारी हैं। उन्हें उनके परंपरागत भोजन से सरकार को वंचित करने का क्या अधिकार है? पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने कहा है कि यह बहुसंख्यकों का जुल्म है। अब वे फैसला करेंगे कि अल्पसंख्यक क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे?

इतेमाद (2 सितंबर) ने अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को निंदा करते हुए कहा

है कि जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, योगी का हिंदुत्व एजेंडा फिर जोर पकड़ रहा है। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। मुसलमानों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि देश के कई नगरों में गोश्त पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हालांकि वहां पर मुसलमान भारी संख्या में रहते हैं। मगर वे इस प्रतिबंध के कारण मांस नहीं खा पाएंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद बड़े पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि मांस और शराब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

टिप्पणी : यह ऐतिहासिक तथ्य है कि विधर्मी शासक विजय प्राप्ति के बाद तलवार के बल पर नगरों के नाम बदलते रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्राबाद रखा था। इसी तरह से तुगलक वंश ने दक्षिण भारत के विख्यात नगर देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा था। मुगलों के शासनकाल में भी हिंदू तीर्थ स्थलों का नाम बदलने का सिलसिला जारी रहा। शाहजहां ने आगरा का नाम बदलकर अकबराबाद और औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा था। इसी तरह से औरंगजेब ने सतारा का नाम बदलकर औरंगाबाद रख दिया था। अब शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम बदलकर सम्भाजी नगर रख दिया है। टीपू सुल्तान ने मैसूर का नाम बदलकर नाजराबाद और मंगलौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। कालीकट का नाम बदलकर इस्लामाबाद किया गया था। मगर बाद में वाडियार वंश के सत्ता में आने के बाद ये नाम बदल दिए गए।

यहां उल्लेखनीय है कि अहमद शाह अब्दाली ने भी मथुरा पर कब्जा करने के बाद उसका नाम इस्लाम नगर और वृंदावन का नाम बदलकर मोहम्मद नगर रखा था। इतिहास के जानकार इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अलीगढ़ का मूल नाम कोल था, जिसे गयासुद्दीन बलबन ने बदलकर अलीगढ़ रखा था। खास बात यह है कि समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने साठ के दशक में देश भर में एक अभियान चलाया था कि अंग्रेजों और विदेशी शासकों के नाम पर रखे गए सड़कों का नाम बदल दिए जाएं और विदेशियों की मूर्तियां हटा दी जाएं। इसके कारण देश की राजधानी दिल्ली में लगभग बीस सड़कों के नाम बदले गए थे और दो दर्जन से अधिक अंग्रेज शासकों की मूर्तियों को भी सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया गया था।

दारूल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाने की मांग

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अगस्त) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद कहा है कि इससे कश्मीर में आतंकवाद को प्रोत्साहन मिल सकता है। तालिबान के तार दारूल उलूम देवबंद और देवबंदी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। भारत में कराड़ों तब्लीगी हैं और उनके कारण यहां तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। तोगड़िया ने भारत सरकार से मांग की है कि तालिबान के विचारों के आधार दारूल उलूम देवबंद, तब्लीगी जमात और जमीयत उलेमा हिंद पर फोरन प्रतिबंध लगाया जाए और उसके सभी मदरसों और मस्जिदां

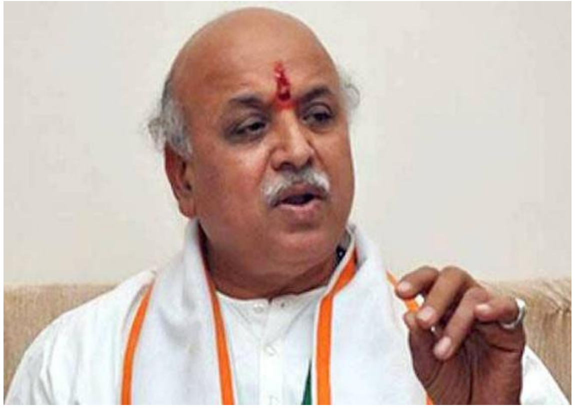

को बंद कर देना चाहिए। वरना भारत आतंकवाद से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि जिसे आतंकवादियों को अपने देश में शरण देने का शौक हो वह उसे पूरा कर सकता है। मगर उसे फ्रांस के अनुभव को याद रखना चाहिए। फ्रांस ने नाइजीरिया के मुसलमानों को शरण दी थो मगर अब उन्हीं मुसलमानों की नई पीढ़ी वहां पर इस्लामिक आतंकवाद का प्रचार कर रही है और लोगों के गले काट रही है। उन्होंने कहा कि तालिबान पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान उनकी मां और दारूल उलूम देवबंद उनका पिता है।

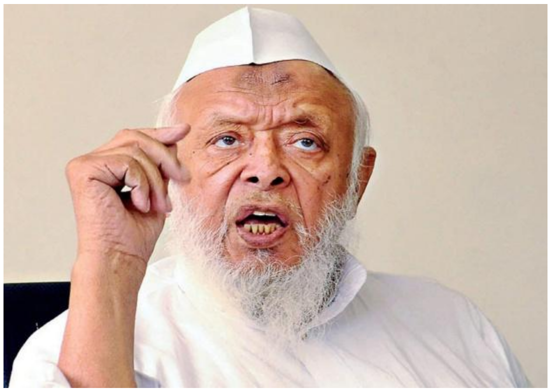

तोगड़िया के बयान पर तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष और दारूल उलूम देवबंद के प्राध्यापक मौलाना अरशद मदनी ने 10 मिनट का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हमने देश की आजादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां की। तुमने क्या किया? वे (तोगड़िया) तालिबान के बारे में यह तो बता रहे हैं कि तब्लीगी जमात उनकी मां है और दारूल उलूम देवबंद उनका पिता। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी है कि तालिबान को तब्लीगी जमात से जोड़ा गया। जबकि वह एक विशुद्ध धार्मिक संस्थान है जो सिर्फ यह बताती है कि जन्नत कैसे हासिल होगी और जहन्नुम से कैसे बचा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने दारूल उलूम देवबंद को बंद करने की मांग की है। शायद उन्हें इस संस्थान का इतिहास मालूम नहीं है। दारूल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हजारों मुस्लिम विद्वानों को अंग्रेजों ने कत्ल किया और उन्हें फांसी पर लटकाया। शेख-उल-हिंद मौलाना मोहम्मद हुसैन को देश से निष्कासित करके माल्टा भेजा गया। देवबंद के हजारों सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की मगर माफी नहीं मांगी। देश की आजादी में देवबंद की भूमिका से कोई इंकार नहीं कर सकता। मैं तोगडिया से यह पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश की आजादी के लिए क्या किया? इस देश की आजादी में आपके पूर्वजों की क्या भूमिका थी? आपको तो पकी-पकाई रोटी मिल गई है। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने आपको कुर्बान कर दिया और कई दशक तक जेलों में रहे उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने का आपको क्या अधिकार है? उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा बिना धार्मिक भेदभाव के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है।

इंकलाब (1 सितंबर) में प्रकाशित समाचार के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ने यह दावा किया है कि संघ परिवार इस देश के फर्जी इतिहास की रचना कर रहा है। इसके लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से मोपला विद्रोह से संबंधित 387 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को हटाने का जा फैसला किया है वह बेहद

दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जंग-ए-आजादी से मुसलमानों की कुर्बानियों को चुन-चुनकर अलग किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को खलनायक के रूप में पेश किया जा सके। पॉपुलर फ्रंट ने केन्द्र सरकार स मांग की है कि मोपला विद्रोह से संबंधित जिन लोगों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से खारिज किया गया था उनका नाम पुनः इस सूची में जोड़ा जाए।

भारत सरकार और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने इन मोपला विद्रोहियों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से इस कारण खारिज किए हैं क्योंकि उन्होंने केरल में हुए साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेकर हिंदुओं की सामूहिक हत्या और लूटपाट की थी। इन दंगों में 2700 से अधिक हिंदू मारे गए थे।

क्या है ऐतिहासिक तथ्य?

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अपने संगठन के इतिहास को जानबूझकर भूल गए हैं। इसलिए उन्होंने अनेक तथ्यों पर कुशलतापूर्वक पर्दा डालने का काम किया है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य उनके इस दावे से बिल्कुल उल्टे हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि दारूल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमा के तार वहाबी सम्प्रदाय से जुड़े हुए हैं। वहाबी सम्प्रदाय की शुरुआत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने की थी। इसका लक्ष्य इस्लाम में व्याप्त गलत रीति-रिवाज को समाप्त करने और इस्लाम को विशुद्ध रूप में पेश करना था। भारत में वहाबी विचारधारा की शुरुआत शाह वली उल्लाह दहलवी ने की जिन्होंने मक्का में अब्दुल वहाब के साथ एक मदरसे में शिक्षा प्राप्त की थी। शाह वली उल्लाह का लक्ष्य भारत को 'दारूल हरब' से बदलकर 'दारूल इस्लाम' (इस्लाम का किला) में परिवर्तित करना था। इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमला करने का आमंत्रण दिया था। उनके निधन के बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज उनके उत्तराधिकारी बने। शाह अब्दुल अजीज के शिष्यों में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही थे। इन दोनों ने 1866 में दारूल उलूम देवबंद की स्थापना की थी। इससे साफ है कि दारूल उलूम देवबंद के तार वहाबी जमात से जुड़े हुए हैं।

अरशद मदनी ने यह भी दावा किया है कि देश की जंग-ए-आजादी में दारूल उलूम देवबंद से जुड़े हुए उलेमा ने सक्रिय भाग लिया था। हालांकि हकीकत यह है कि इस संगठन से जुड़े हुए उलेमा वहाबी थे और उनका लक्ष्य भारत में इस्लामिक राज्य की पुनर्स्थापना करना था। उदाहरण के रूप में बंगाल में तितुमीर ने इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए युद्ध प्रारंभ किया और नदीया के जमींदार राजा कृष्णदेव राय के किले पर कब्जा करके वहां इस्लामिक झंडा लहरा दिया। बिहार और पंजाब में भी वहाबी आंदोलन का एक मात्र लक्ष्य इस्लामिक राज्य की भारत में स्थापना था। जमीयत उलेमा का देश के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार होने के लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं। जमीयत उलेमा के नेताओं ने ही खिलाफत कमेटी की स्थापना की थी। 1919 में दिल्ली में जारी खिलाफत घोषणापत्र में देश की आजादी का कोई उल्लेख नहीं है। घोषणापत्र में तीन मांगें मुख्य थीं। उस्मानिया सल्तनत का विघटन न किया जाए। खलीफा के पद को बरकरार रखा जाए और मक्का मदीना का नियंत्रण खलीफा के हाथ में रहे। इसी खिलाफत कमेटी ने बाद में जमीयत उलेमा का रूप लिया था। देश के विभाजन के बाद जमीयत उलेमा में विभाजन हुआ और एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान चला गया। वहां पर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम नामक नया संगठन स्थापित किया। इस संगठन से जुड़े हुए चार मुख्य

आतंकवादी संगठन हैं, जिनमें लश्कर-ए-झंगवी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिपाह-ए-सहाबा और अफगान तालिबान शामिल हैं। इससे साफ है कि तालिबान के साथ देवबंदी जमात के तार जुड़े हुए हैं।

जहां तक तब्लीगी जमात का संबंध है इसकी स्थापना 1926 में आर्य समाज द्वारा प्रारम्भ किए गए 'शुद्धि आंदोलन' को विफल बनाने के लिए की गई थी। इसके नेताओं में मौलाना आजाद, अल्लामा इकबाल, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन, मुफ्ती किफायतुल्लाह आदि अनेक मुस्लिम विद्वान शामिल थे। आज यह संगठन संसार के 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और इसके अनुयायियों की संख्या दस करोड़ बताई जाती है।

मस्जिदों में नमाज पढ़ने का विवाद

दिल्ली की मस्जिदों में नमाज पढ़ने का विवाद गंभीर रूप धारण कर रहा है। यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान लाइव के अनुसार 26 अगस्त को भारी संख्या में नमाजो फिरोज शाह कोटला में नमाज अदा करने के लिए गए थे। मगर उनको पुलिस ने नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह ने दो दिन पूर्व लोगों को यह आश्वासन दिया था कि मस्जिदों में उन्हें नमाज अदा करने की अनुमति होगी। मगर जब जुमा के दिन लोग नमाज अदा करने के लिए वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मस्जिद में जाने और नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह ने यह सफाई दी है कि क्योंकि उपराज्यपाल ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर कोरोना महामारी के कारण प्रतिबंध लगा रखा है इसलिए फिलहाल नमाजियों को मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास के कारण पुलिस ने केवल मस्जिदों के इमामों और अन्य कर्मचारियों को ही मस्जिद में जाने और वहां पर सफाई वगैरह करने की अनुमति दी है।

इंकलाब (31 अगस्त) के अनुसार पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज

अदा करने की मांग पुन: उठने लगी है। इंकलाब ने लिखा है कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह खिड़की मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दे। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पुरातत्व विभाग के स्मारकों से संबंधित नियमों में यह साफ लिखा हुआ है कि जो स्मारक पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है उनके स्वरूप और इस्तेमाल को बदला नहीं जा सकता। समाचारपत्र ने लिखा है कि यदि नमाजियों को नमाज अदा करने की अनुमति नहीं है तो वहां पर प्रदर्शनियों, समारोहों और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति क्यों दी जाती है?

हालांकि सच्चाई यह है कि भारतीय संसद में अनेक बार सरकार इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि केवल उन्हीं उपासना स्थलों में उपासना को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें जब उनका अधिग्रहण किया गया हो तो उस समय उनमें लोग उपासना करते रहे हों। विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में इस मामले में संसद में अनेक बार चर्चा हुई थी और सरकार ने यह स्वीकार किया था कि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के तहत देश में 265 मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ऐसे हैं जिनमें उपासना करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि जब इनका अधिग्रहण किया गया था तो उस समय उनमें उपासना नहीं होती थी।

जहां तक देश की राजधानी दिल्ली का संबंध है वहां पर गत कई दशक से विभिन्न मुस्लिम संगठन इस बात का अभियान चला रहे हैं कि उन्हं ऐतिहासिक मस्जिदों में जो भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में हैं नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। चार दशक पूर्व राजधानी में मुसलमानों द्वारा इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसे मुस्लिम मजलिस मुशावरात, जमीयत उलेमा, जमात-ए-इस्लामी, शिया काउंसिल आदि का समर्थन प्राप्त था। इस संबंध में जामा मस्जिद के तत्कालीन शाही इमाम स्वगीय मौलाना सैयद अब्दुल्लाह बुखारी ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया था। मुसलमानों के बढ़ते हुए दबाव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय के विदेश मंत्री नरसिम्हा राव को इस विवाद का हल निकालने के लिए नियुक्त किया था। इस बैठक में नरसिम्हा राव के अतिरिक्त शिक्षा मंत्री शीला कौल और अनेक मुस्लिम नेता जैसे सैयद अहमद हासमी, सी.के. जाफर शरीफ, गुलाम नबी आजाद, सैयद शहाबुद्दीन, मौलाना अहमद अली, गुलाम महमूद बनातवाला, अमीरूल हसन रिजवी आदि ने भाग लिया था। मगर इस बैठक में यह विवाद सुलझाया नहीं गया। मुसलमानों की भीड़ ने सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए सफदरजंग और अनेक ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाज अदा करनी शुरू कर दी। पुरातत्व विभाग ने उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाए। मगर राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस निष्क्रिय बनी रही। सैयद शहाबुद्दीन के अनुसार शाही मस्जिद सफदरजंग और 20 अन्य ऐतिहासिक मस्जिदों में मुसलमानों ने नमाज अदा करनी शुरू कर दी थी मगर बाद में सरकार ने इसे बंद करवा दिया। अब मुस्लिम नेता पुन: इस मामले को गरमा रहे हैं। नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्शन काउंसिल के महासचिव मोहम्मद सलीम का कहना है कि मुसलमानों को प्राचीन मस्जिदों में नमाज अदा करने का अधिकार दिलाने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जा रहा है। ताजमहल और कुछ अन्य स्मारकों में कोरोना काल से पूर्व मुसलमानों को बिना टिकट लिए जुमा को नमाज अदा करने की छूट दी गई थी। ■

उत्तर प्रदेश के बारह जिलों में खुलेंगे एटीएस कमांडो सेंटर

इंकलाब (19 अगस्त) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बारह जिलों में आतंकवाद विरोधी केन्द्र खोलने का फैसला किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि जिन जिलों में ये केन्द्र खोले जा रहे हैं उनमें देवबंद, बहराइच, श्रावस्ती, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, आजमगढ़ आदि शामिल हैं। देवबंद में आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पहले से ही एक कार्यालय काम कर रहा है। इसकी स्थापना तीन वर्ष पूर्व तब की गई थी जब इस इलाके में एक दर्जन से अधिक विदेशी जासूस जिनके तार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे पकड़े गए थे। गुप्तचर विभाग ने यह भी दावा किया था कि देवबंद में देश में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का कार्य अनेक गिरोह कर रहे हैं। इस पर देवबंद में कई जगह पर छापे मारे गए थे।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस घोषणा के बाद विपक्ष ने योगी सरकार को अपना निशाना बनाना शुरू किया है। विपक्ष की बयानबाजी के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने संवाददाताओं को बताया कि योगी सरकार ने आतंकवाद निरोधक विभाग को और सक्रिय बनाने का फैसला किया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय और गुप्तचर विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के एक दर्जन से अधिक जिलों में एटीएस के कमांडो सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए इन जिलों में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और उनका निर्माण कार्य भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां पर स्टाफ की भी नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि देवबंद, सहारनपुर, बहराइच, श्ररावस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में एटीएस की यूनिटें स्थापित कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त वाराणसी और झांसी में भी ये केन्द्र स्थापित होंगे। इन दोनों जगहों पर इन केन्द्रों के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। अवस्थी ने यह स्पष्ट किया कि हर केन्द्र में 15-20 प्रशिक्षित अधिकारी होंगे। इनका संचालन एनएसजी के तर्ज पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एटीएस की स्थापना 2017 में की गई थी, जिसके स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईबी के अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई थी।

अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी सैनिक भी वापस

सियासत (1 सितंबर) के अनुसार 20 वर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ा है। 31 अगस्त को उसने अपने सभी फौजियों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है और अमेरिकी सेना का विमान अमेरिकी राजदूत और अन्य स्टाफ को लेकर अफगानिस्तान से रवाना हो गया। समाचारपत्र के अनुसार अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद तालिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अमेरिकी सरकार के आकड़ों के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान में 23 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं और उसके ढ़ाई हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। अमेरिकी सैनिक अक्टूबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक वहां पर डेरे डाले हुए थे। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अभी कुछ अमेरिकी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। अमेरिका की ओर से इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन का जो कार्यक्रम तैयार किया गया था उसकी अवधि में कुछ विस्तार किया जाए। मगर तालिबान के कड़े रूख के कारण अमेरिका को इसमें सफलता नहीं मिली। तालिबान ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूर्णतः अपने हाथ में ले लिया है और यह घोषणा की है कि अब अफगानिस्तान को पूरी आजादी प्राप्त हो गई है। तालिबान ने काबुल में हवाई फायर करके अमेरिका के जाने का स्वागत किया है।

सियासत (29 अगस्त) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि अफगान तालिबान का प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा के बारे में आज भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। व आम तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर नजर नहीं आते। अफगानिस्तान में तालिबान के

प्रमुख मुल्ला उमर की हत्या के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था जो कि बाद में एक अमेरिकी हमले में मारे गए थे। 2016 में हिबतुल्लाह को नया अमीर नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों से हिबतुल्लाह सार्वजनिक रूप से कभी दिखाई नहीं दिए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद से जब तालिबान के प्रमुख के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर गुप्त स्थान पर रखा गया है। वे आमतौर पर कंधार में रहते हैं और किसी भी विदेशी नेता या तालिबान से मिलने से बचते हैं।

अवधनामा (18 अगस्त) न यह दावा किया है कि अफगानिस्तान में सरकार के गठन का प्रयास चल रहा है और शीघ्र ही इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण घोषणा की जाएगी। अवधनामा ने अपने संपादकीय में यह भी कहा है कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करे और वहां पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें जारी रखा जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 सितंबर) ने इस समाचार को मुख्य समाचार बनाया है और इसका शीर्षक दिया है– "बड़े बेआबरू होकर अमेरिकी विदा हुए। पूरे अफगानिस्तान में जश्न का माहौल, हर मस्जिद में सजदा शुक्र और हवाई फायरिंग। तालिबान की ओर से दुनिया भर के मुसलमानों के नाम अपील कि वे इजरायल के खिलाफ एकजुट होकर यरुशलम को यहूदियों के कब्जे से आजाद कराएं।"

इसी समाचारपत्र ने 19 अगस्त के अंक में यह भविष्यवाणी की है कि अमेरिका के जाते ही आईएसआईएस भी तालिबान से युद्ध समाप्त कर देगा। क्योंकि आईएसआईएस अमेरिका की कठपुतली है। तुर्की ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली है और राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह घोषणा की है कि काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का भार अब तुर्की नहीं संभालेगा।

जर्मनी द्वारा अफगानिस्तान को सहायता देने से इंकार

इत्तेमाद (18 अगस्त) के अनुसार जर्मनी ने यह घोषणा की है कि वह अफगानिस्तान में काबिज तालिबान को भविष्य में किसी तरह की सहायता नहीं देगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि जर्मनी द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए अफगानिस्तान को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी वह बंद कर दी गई है। हम इन विकास परियोजना में लगे हुए जर्मन नागरिकों और एनजीओ से संबंधित कार्यकर्ताओं को वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जर्मनी द्वारा अफगानिस्तान को प्रत्येक वर्ष 504 मिलियन डॉलर की सहायता दी जाती थी जो कि सबसे ज्यादा थी। जर्मन सैनिक भी नाटो की गठबंधन के कारण वहां पर सैनिक गतिविधियों में भाग ले रहे थे।

अफगानिस्तान में सह शिक्षा पर प्रतिबंध

इत्तेमाद (22 अगस्त) के अनुसार तालिबान ने देश में सह शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि सह शिक्षा के कारण अनेक सामाजिक बुराईयों का जन्म हुआ है। खामा प्रेस एजेंसी के अनुसार यह फैसला तालिबान अधिकारियों और विभिन्न विश्व विद्यालयों के कुलपतियों की संयुक्त बैठक में किया गया है। इस बैठक के बाद तालिबान के प्रवक्ता मुल्ला फरीद ने कहा कि इस्लाम में सह शिक्षा की कोई कल्पना नहीं है और यह सभी सामाजिक बुराईयों की जड़ है। लड़के-लड़कियों के साथ पढ़ने से अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस्लाम के सिद्धांतों को लागू किया जाए और सह शिक्षा पर रोक लगाई जाए। अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्षों से सह शिक्षा का चलन था। तालिबान के इस फैसले से 40 हजार छात्राएं और 2000 महिला प्राध्यापक प्रभावित होंगे।

इत्तेमाद (24 अगस्त) के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान में शरिया को लागू किया जाएगा। क्योंकि शरिया कानून की सजाओं से ही अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो सकती है। पंजशीर का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि तालिबान युद्ध नहीं चाहते। हमारा यह प्रयास है कि सभी विवाद बातचीत से हल हो जाएं। वहां के अनेक लोगों ने हमें यह संदेश भेजा है कि वे बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहते हैं और युद्ध नहीं चाहते। हक्कानी संगठन के नेता खलीकुर रहमान हक्कानी ने कहा है कि अब अफगानिस्तान में किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। हम अफगानों को शांतिपूर्ण वातावरण देना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो इस्लामिक हुकूमत स्थापित होगी उसमें सभी बिरादरी के लोग शामिल होंगे और उसे इस्लाम के मुताबिक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, उनके सहायकों, सलाहकारों और अफगान सेना के सेनापतियों के खिलाफ भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम अपनी तरफ से सबको माफ करते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध हम पर विदेशियों ने लादा था जो अफगान बिरादरी में भेदभाव पैदा करना चाहते थे। अब वे चले गए हैं और हम अमन चाहते हैं।

हमारा समाज ने 28 अगस्त के संपादकीय में कहा है कि अफगानिस्तान गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। तालिबान विरोधी यह नहीं चाहते कि तालिबान देश पर शासन करें। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां पर हिंसा का वातावरण बन रहा है और वहां पर खून की होली खेलने की संभावना है। काबुल में जो 200 से अधिक लोग मारे गए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। जरूरत इस बात की है कि भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाएं न हों। समाचारपत्र ने आईएसआईएस से अपील की है कि वह मुसलमानों का खून बहाना बंद कर दे।

तालिबान का धार्मिक प्रमुख

मुंबई उर्दू न्यूज (2 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी समाचारपत्रों ने दावा किया है कि ईरान की तरह तालिबान ने भी अपना धार्मिक प्रमुख चुनने का प्रयास तेज कर दिया है। संभवत: उनका सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा होंगे। वे प्रारंभ से ही कंधार में रहत हैं। पंजशीर में तालिबान और वहां के नॉर्दन अलायंस के बीच जो समझौता वार्ता चल रही थी वह विफल हो गई है और वहां पर दोनों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। इन झड़पों की पुष्टि अफगान मीडिया ने की है। इन झड़पों में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने कहा है कि तालिबान ने पंजशीर के शोतुल जिला में अलायंस की पांच चौकियों पर कब्जा कर लिया है और वह आगे बढ़ गया है। तालिबान के प्रवक्ता ने पंजशीर के नागरिकों के नाम एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जो वार्तालाप चल रहा था वह विफल हो गया है और अब युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है।

अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन पर प्रतिबंध

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अगस्त) के अनुसार तालिबान ने यह घोषणा की है कि भविष्य में देश में अफीम की खेती करने की अनुमति नहीं होगी। अफगानिस्तान में सरकार की आय का एक मुख्य साधन अफीम और अन्य मादक पदार्थ हैं, जिनकी दुनिया भर में तस्करी की जाती है। तालिबान द्वारा पोस्त की खती पर प्रतिबंध के कारण विश्व भर में अफीम, चरस और कोकीन के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। तालिबान के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि नशीले पदार्थों का उत्पादन करना या उनका व्यापार करना शरा के खिलाफ है।

चीन में तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति

रोजनामा सहारा (21 अगस्त) के अनुसार चीन ने अपने नागरिकों को तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संदर्भ में कानून पारित किया जा चुका है। इससे पूर्व चीनी सिर्फ दो बच्चे ही पैदा कर सकते थे। यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि चीन में जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर गिरावट आ रही है। चाईना डेली की रिपोर्ट के अनुसार सरकार टैक्स कम कर रही है और बीमा, शिक्षा, आवास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर रही है। ताकि लोगों पर तीसरे बच्चे का बोझ कम पड़े। 2016 तक चीनियों को सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की अनुमति थी। बाद में जनसंख्या वृद्धि दर में आई कमी के कारण नागरिकों को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई थी। चीन सरकार का दावा है कि सरकार ने बच्चे पैदा करने पर जो प्रतिबंध लगाया था उसके कारण 40 करोड़ बच्चों की पैदाइश को रोका गया है। इस समय चीन की जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ बताई जाती है।

उमरा करने की अनुमति

रोजनामा सहारा (31 अगस्त) के अनुसार सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि अगले महीने से दुनिया भर के मुसलमानों को उमरा करने की अनुमति होगी। कोरोना महामारी के कारण जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे हटा लिए गए हैं। हज मंत्रालय के उप मंत्री ने अरब न्यूज को बताया कि उमरा करने वालों के लिए देश भर के हाटल खोल दिए गए हैं और उनमें ठहरने वालों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी भी व्यक्ति को उमरा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन उमरा का वीजा इच्छुक व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले यात्रो स्मार्ट कार्ड एप्प का भी लाभ उठा सकते हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार विदेशों से उमरा यात्रियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। डेढ़ वर्ष पूर्व सऊदी सरकार ने हज और उमरा पर कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंध लगाया था। समाचारपत्र के अनुसार उमरा करने के लिए आने वाले सभी इच्छुक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र वीजा का प्रार्थना पत्र देते हुए पेश करना होगा। इसके बाद ही उन्हें सऊदी अरब में आने की अनुमति दी जाएगी। उमरा और हज से सऊदी अरब को दस बिलियन डॉलर की आय प्रति वर्ष फीस के रूप में होती है। प्रत्येक वर्ष 80 लाख से लेकर 1 करोड़ व्यक्ति उमरा करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि हज सिर्फ एक महीने के भीतर ही किया जा सकता है जबकि उमरा में अवधि का कोई प्रतिबंध नहीं है और उमरा करने वाले कभी भी आकर उमरा कर सकत हैं।

यमन में हूती विद्रोहियों का हमला

इंकलाब (30 अगस्त) के अनुसार दक्षिणी यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और उसके सहायक देशों के सैनिक हवाइ अड्डे को मिसाइल और ड्रोन हमले से निशाना बनाया, जिसमें कम-से-कम 30 सैनिक मारे गए और 60 घायल हो गए। संवाद समिति के अनुसार यह हवाई अड्डा लाहिज प्रदेश के अल-अनद में स्थित है। बताया जाता है कि इन हमलों की शुरुआत बैलिस्टिक मिसाइल से हुई और यह मिसाइल उस समय वहां गिरे जब सैनिक खाना खा रहे थे। सैनिक प्रवक्ता ने कहा है कि इन हमलों के पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ है। 2014 से ही विद्रोहियों और सऊदी सैनिकों के बीच झड़पों का सिलसिला जारी है। अब तक दस हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह हूती विद्रोहियों को सैनिक सहायता देना फौरन बंद करे। वरना उसे गंभीर परिणामों को भुगतना होगा।

मलेशिया के नए प्रधानमंत्री

इंकलाब (28 अगस्त) के अनुसार मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने सत्ता संभाल ली है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं रखा है। नए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि यह उनका परीक्षाकाल है। क्योंकि मलेशिया कोरोना और उसके कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने सभी मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों से आग्रह किया है कि वे मितव्ययिता का अभियान चलाएं ताकि आर्थिक संकट से उभरा जा सके। प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और उनसे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सहयोग मांगा है। मलेशिया के राजा सुल्तान अहमद अब्दुल्ला ने नए प्रधानमंत्रो को यह निर्देश दिया है कि वे संसद में विश्वासमत प्राप्त करें। संसद का अधिवेशन इस महीने के अंत में शुरू हो रहा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार इस्लामिक संगठन हमास के प्रमुख इस्माइल हनीयेह ने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भेजा है और उनसे आग्रह किया है कि वे इजरायल के खिलाफ अभियान में उनका समर्थन करें और सहयोग दें।

माली के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार

इंकलाब (28 अगस्त) के अनुसार अफ्रीकी देश माली क पूर्व प्रधानमंत्री बौबेये माइगा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के शासनकाल में विदेशों से जो विमान खरीदे गए थे, उसमें करोड़ों डॉलर की हेराफेरी हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने इस सौदे में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत ली थी। जब इब्राहिम बाउबकर चुनाव में हारे तो नई सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाई थी, जिसमें राष्ट्रपति के अतिरिक्त पूर्व प्रधानमंत्री भी दोषी पाए गए थे।

सऊदी अरब और रूस के बीच सैनिक संधि

रोजनामा सहारा (25 अगस्त) के अनुसार सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार सऊदी अरब और रूस के बीच सैनिक समझौता हुआ है, जिसमें यह तय किया गया है कि सैनिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढाया जाए। इस संधि पर सऊदी अरब के उप रक्षामंत्री खालिद बिन सलमान और रूसी उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता रूस में हुआ है। समझौते पर हस्ताक्षर से पूर्व उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सैनिक सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है।

मिस्र में पार्ट टाइम शादी पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (25 अगस्त) के अनुसार मिस्र की शरिया काउंसिल ने पार्ट टाइम मैरिज पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि यह इस्लाम के निकाह के दृष्टिकोण के खिलाफ है और यह इस्लाम के अनुसार हराम है। मिस्र और कुछ अन्य अरब देशों में गत कुछ समय से एक निर्धारित अवधि तक निकाह करने का रूझान बढ़ रहा था। इस अवधि के गुजरने के बाद दोनों पति-पत्नी एक दूसरे को तलाक दे देते थे और इस बात का उल्लेख उनके बीच हुए निकाहनामे में भी किया जाता था। शरिया काउंसिल ने कहा है कि इससे अनेक तरह की परेशानियां पैदा हो रही हैं और इससे अवैध रिश्तों में भारी वृद्धि हुई है। भविष्य में मिस्र में जो निकाह होंगे वह इस्लामिक शरा के अनुसार होंगे और उनमें निर्धारित अवधि का कोई उल्लेख नहीं होगा। अगर किसी निकाह में निर्धारित अवधि का उल्लेख होगा तो वह इस्लाम के अनुसार हराम होगा और ऐसा निकाह करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस का बदरूद्दीन अजमल की पार्टी से संबंध विच्छेद

इंकलाब (31 अगस्त) के अनुसार असम का विपक्षी महागठबंधन टूट गया है। असम कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि वह बदरूद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से भविष्य में कोई संबंध नहीं रखेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात पर हैरानो प्रकट की है कि अजमल अब भाजपा से गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कांग्रेस हाईकमान को भी सूचित कर दिया गया है। इस वर्ष राज्य विधान सभाओं के चुनाव से पूर्व कांग्रेस के नेतृत्व में दस विपक्षी दलों का एक महागठबंधन बनाया गया था, जिसमें ये दोनों पार्टियां भी शामिल थीं। ■

22 हजार से अधिक मदरसा अध्यापक वेतनमान से वंचित

इंकलाब (29 अगस्त) के अनुसार मदरसा काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद उन्नस ने राष्ट्रपति, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री को एक ज्ञापन भेजकर यह आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार द्वारा पोषित उत्तर प्रदेश के 7700 मान्यता प्राप्त मदरसों के 22000 अध्यापकों को पिछले चार वर्षों से वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है कि इनके वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के 7000 से अधिक मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया था और उन्हें नया वेतन क्रम देने का आश्वासन दिया गया था। मगर पिछले 4 वर्षों से उन्हें नया वेतनमान नहीं दिया गया जिससे वे आर्थिक बदहाली का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अध्यापक सामुहिक भूख हड़ताल करेंगे। ■

सिकंदर बख्त की मजार पर श्रद्धांजलि सभा

हमारा समाज (25 अगस्त) के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय सिकंदर बख्त की कब्र पर राष्ट्रीय मंच की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मंच के अध्यक्ष जमालुद्दीन सिद्दीकी, हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तनवीर अहमद आदि नेता शामिल थे। सिकंदर बख्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे और वे चांदनी चौक क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले पहले मुस्लिम उम्मीदवार था। जमालुद्दीन सिद्दीकी ने मांग की कि दिल्ली की किसी सड़क का नाम सिकंदर बख्त के नाम पर रखा जाए।

मुस्लिम विद्वानों से टीवी चैनलों का बहिष्कार करने की अपील

इंकलाब (23 अगस्त) के अनुसार उत्तराखंड हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने मुस्लिम विद्वानों से अपील की है कि वे टीवी चैनलों का बहिष्कार करें। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद मीडिया इस मामले को साम्प्रदायिक रंग दे रहा है और टीवी चैनलों पर मुस्लिम नेता और धार्मिक मौलाना जो कुछ कहते हैं उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है। इससे मुसलमानों को नुकसान होता है और उनके खिलाफ वातावरण बनता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया में जो मुस्लिम विरोधी तत्व हैं वे अफगानिस्तान की घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए वे मुसलमानों का सहारा ले रहे हैं।

ब्रिटेन से ताजिया का मॉडल मंगवाने की मांग

औरंगाबाद टाइम्स (20 अगस्त) ने भारत सरकार से मांग की है कि हैदराबाद के निजाम के शासनकाल के दौरान हीरों से जड़ा हुआ एक ताजिया का मॉडल तस्कर ब्रिटेन ले गए थे। अब उसे वहां नीलाम किया जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस ताजिया और झंडे का प्रदर्शन हैदराबाद की ऐतिहासिक बीबी-का-अलावा के जुलूस में किया जाता था। इस्लामिक संस्कृति और धर्म का यह प्रतीक कई शताब्दी पुराना है इसलिए वह राष्ट्रीय धरोहर है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

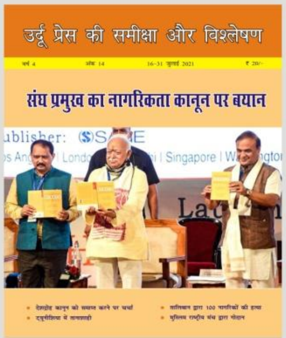

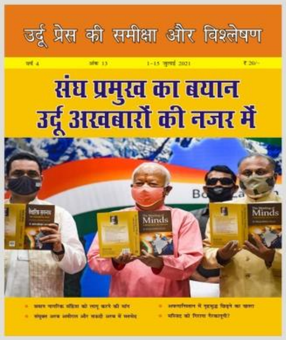

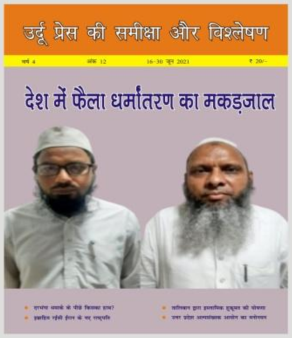

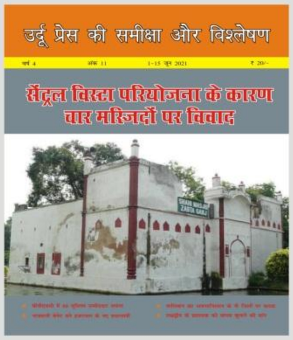

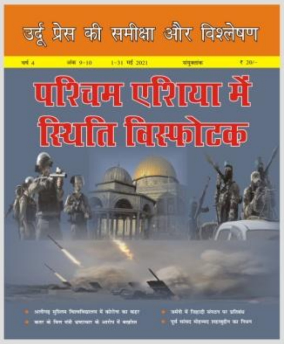

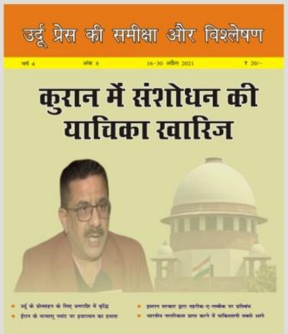

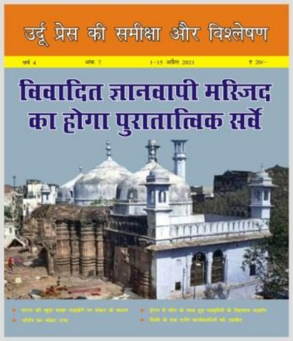

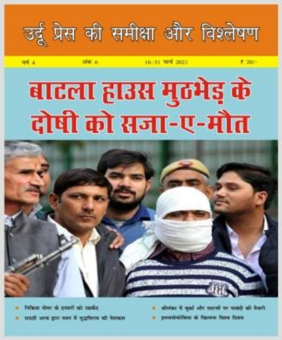

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in